

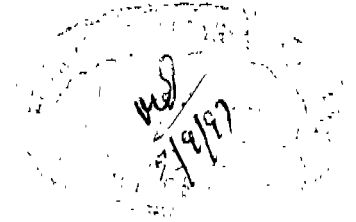


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 244]
No. 244]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अप्रैल 10, 1997/चैत्र 20, 1919
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 10, 1997/CHAITRA 20, 1919

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 318 (अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986) (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 60 (अ), तारीख 7 जनवरी, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) केन्द्रीय सरकार जब तक उस सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति न दे दी गई हो तब तक किसी परियोजना के किसी क्रियाकलाप के विस्तार या आधुनिकीकरण या आरंभ किए जाने के संबंध में कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित करती है।

और उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम 4 में यह उपबंध है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुखित दे सकेगी।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना का अभिमुखित देना लोकहित में है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त

अधिसूचना में और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

(1) पैरा 2 में—

(क) उप पैरा i में, मद (क) में "और पर्यावरण प्रबंध योजना" शब्दों के स्थान पर "पर्यावरण प्रबंध योजना और अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट लोक सुनवाई का ब्यौरा" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप पैरा iii में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) प्रभाव निर्धारण अधिकरण परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों और आंकड़ों जो स्थलों अथवा कारखानों में यात्राओं के दौरान, यदि लोक सुनवाई के ब्यौरे लिए गए हैं, संग्रहीत आंकड़ों द्वारा अनुपूरित होंगे, के तकनीकी निर्धारण और प्रभावित जनसंख्या की और यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संबंधी समूहों की अन्तः क्रिया पर आधारित सिफारिशें तैयार करेगा।

निर्धारण परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेजों और आंकड़ों की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर और जहां लोक सुनवाई की समाप्ति पर पूरा किया जाएगा और विनिश्चय उसके पश्चात् तीस दिन के भीतर सूचित किया जाएगा।

दी गई अनापत्ति परियोजना के सन्निर्माण या संक्रिया के प्रारंभ होने से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमाम्य होगी।

(2) अनुसूची 1 में, मद 21 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

सिवाय ऐसे विकास कार्यों के जिसमें विद्यमान संरक्षण के साथ सीमान्त भूमि अर्जन पर सड़कों का चौड़ा किया जाना और उसे सुदृढ़ किया जाना भी सम्मिलित है, परन्तु यह पारिस्थितिकी संवेदनशील इलाके जैसे राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य बाघ आरक्षित, आरक्षित वनों से होकर नहीं गुजरती हो।

(3) अनुसूची 3 के पश्चात् अन्त में निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी अर्थात् :—

“अनुसूची-4

[पैरा 2, उप पैरा (1) देखिए]

लोक सुनवाई के लिए प्रक्रिया

(1) लोक सुनवाई की प्रक्रिया—जो कोई परियोजना के पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा वह संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेजों के बीस सैट प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

- (1) एक कार्यपालक सार, जिसमें परियोजना की मुख्य बातें अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में होंगी।
- (2) जहां मल की निस्सारण, व्यापार बहिस्त्रोव, जल-संसाधन किसी रूप में अपेक्षित है वहां जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1985 के अधीन विहित प्ररूप-XIII
- (3) जहां किसी प्रसंस्करण, संक्रिया या उद्योग में उत्सर्जन का उन्मोचन अन्तर्वर्तित है वहां वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संघ राज्यक्षेत्र नियम, 1983 के अधीन विहित प्ररूप-1।
- (4) कोई अन्य जानकारी या दस्तावेज, जो बोर्ड की राय में आवेदन के संबंध में उनके अन्तिम निपटारे के लिए आवश्यक है।

(2) लोक सुनवाई की सूचना :—

(i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण संबंधी लोक सुनवाई की सूचना देगा, जो परियोजना के आस-पास के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो समाचारपत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिनमें से एक संबंधित स्थान की जन भाषा में होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लोक सुनवाई की परियोजना के आस-पास की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख करेगा। अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर जनता के सुझाव, विचार टीका-टिप्पणियां और आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे।

(ii) ऐसे सभी व्यक्ति, जिनमें वास्तविक निवासी, पर्यावरण संबंधी समूह और परियोजना स्थल/विस्थापन स्थल/स्थलों पर स्थित अन्य व्यक्ति भी हैं, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, लोक सुनवाई में भाग ले सकते हैं। वे राज्य प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड को मौखिक/लिखित सुझाव भी दे सकते हैं।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजन के लिए व्यक्ति से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

- (क) कोई व्यक्ति जिसके पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के दिए जाने से प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) कोई व्यक्ति जो ऐसी परियोजना का, जिसकी बाबत पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, स्वामी है या उस पर उसका नियंत्रण है;

(ग) व्यक्तियों का ऐसा कोई संगम, चाहे निगमित हो या नहीं जिसके पर्यावरण के क्षेत्र में परियोजना और/या कार्यकरण से प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) किसी भाग के भीतर, जिसकी स्थानीय सीमाएं ऐसे पड़ोस के अन्तर्गत है जिसमें परियोजना को लगाए जाने का प्रस्ताव है, कोई स्थानीय प्राधिकरण।

(3) लोक सुनवाई पैनल की संरचना :—लोक सुनवाई पैनल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- (i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि;
- (ii) जिला कलक्टर या उसका नामनिर्देशित;
- (iii) विद्युत के विषय पर कार्रवाई करने वाले राज्य सरकार के प्रतिनिधि;
- (iv) पर्यावरण के विषय पर कार्रवाई करने वाले राज्य सरकार के प्रतिनिधि;
- (v) नगरपालिकाओं या पंचायतों जैसी स्थानीय निकायों के तीन से अनधिक प्रतिनिधि;
- (vi) जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले क्षेत्र के तीन से अनधिक ज्येष्ठ नागरिक।

(4) कार्यपालक तक पहुंच :—संबंधित व्यक्तियों की निम्नलिखित स्थानों पर परियोजना के सार तक पहुंच की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात् :—

- (i) जिला कलक्टर का कार्यालय;
- (ii) जिला उद्योग केन्द्र;
- (iii) जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या, यथास्थिति, नगर निगम/स्थानीय निकाय के आयुक्त के कार्यालय में;
- (iv) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय या इसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में;
- (v) पर्यावरण के विषय पर कार्रवाई करने वाले राज्य सरकार के संबंधित विभाग में।

[सं. जेड-12013/14/89-आई.ए. 1]

आर. एच. ख्वाजा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना, का.आ. 60 (अ), दिनांक जनवरी, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् का.आ. 356 (अ), दिनांक 4 मई, 1994 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 1997.

S. O. 318(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 60(E), dated the 7th January, 1994 (hereinafter referred to as the said notification) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government imposed certain restrictions and prohibitions on the expansion and modernisation of any activity or the undertaking of any project, unless environment clearance has been granted by the Government;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said rules provides that, whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Act read with sub-rule (4) of rule 5 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely :—

in the said notification,—

(1) in paragraph 2,—

(a) in sub-paragraph I, in item (a), for the words “and an environment Management Plan”, “पर्यावरण प्रबंधक योजना” the words, “Environment Management Plan and details of public hearing as specified in Schedule IV” shall be substituted;

(b) in sub paragraph III, for item (c), the following shall be substituted, namely :—

“(c) the Impact Assessment Agency shall prepare a set of recommendations based on the technical assessment of documents and data furnished by the project authorities and supplemented by data collected during visits of sites of factories, if undertaken and details of public hearing.

The assessment shall be completed within a period of ninety days from receipt of the requisite documents and data from the project authorities and completion of public hearing and decision conveyed within thirty days thereafter.

The clearance granted shall be valid for a period of five years from commencement of the construction or operation of the project.”

(2) in Schedule-I, for item 21, the following item shall be substituted, namely:— “Highway Projects except projects relating to improvement work including widening and strengthening of roads with marginal land acquisition along the existing alignments provided it does not pass through ecologically sensitive areas such as National Parks, Sanctuaries, Tiger reserves, Reserve forests”.

(3) after Schedule-III, the following Schedule shall be added at the end, namely :—

“SCHEDULE IV

(See sub-para I of para 2)

Procedure for Public Hearing

(1) **Process of Public Hearing** :—Whoever apply for environmental clearance of projects, shall submit to the concerned State Pollution Control Board twenty sets of the following documents namely :—

- (i) An executive summary containing the salient features of the project both in English as well as local language.
- (ii) Form XIII prescribed under Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975 where discharge of sewage, trade effluents, treatment of water in any form, is required.
- (iii) Form I prescribed under Air (Prevention and Control of Pollution) Union Territory Rules, 1983 where discharge of emissions are involved in any process, operation or industry.
- (iv) Any other information or document which is necessary in the opinion of the Board for their final disposal of the application.

(2) **Notice of Public Hearing** :—

- (i) The State Pollution Control Board shall cause a notice for environmental public hearing which shall be published in at least two newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned. State Pollution Control Board shall mention the date, time and place of public hearing. Suggestions, views, comments, and objections of the public shall be invited within thirty days from the date of publication of the notification.
- (ii) All persons including bona fide residents, environmental groups and others located at the project site/sites of displacement/sites likely to be affected can participate in the public hearing. They can also make oral/written suggestions to the State Pollution Control Board.

Explanation :—For the purpose of the paragraph person means,—

- any person who is likely to be affected by the grant of environmental clearance;
- any person who owns or has control over the project with respect to which an application has been submitted for environmental clearance;
- any association of persons whether incorporated or not likely to be affected by the project and/or functioning in the field of environment;
- any local authority within any part of whose local limits is within the neighbourhood, wherein the project is proposed to be located.

(3) **Composition of public hearing panel :—**The composition of Public Hearing Panel may consist of the following, namely:—

- Representative of State Pollution Control Board;
- District Collector or his nominee;
- Representative of State Government dealing with the subject;
- Representative of Department of the State Government dealing with Environment;
- Not more than three representatives of the local bodies such as Municipalities or panchayats;
- Not more than three senior citizens of the area nominated by the District Collector.

(4) **Access to the Executive Summary:—**The concerned persons shall be provided access to the Executive Summary of the Project at the following places namely:—

- District Collector Office;
- District Industry Centre;
- In the Office of the Chief Executive Officers of Zila Parishad or Commissioner of the Municipal Corporation/Local body as the case may be;
- In the head office of the concerned State Pollution Control Board and its concerned Regional Office;
- In the concerned Department of the State Government dealing with the subject of environment”.

[No. Z-12013/4/89-IA.I]

R.H. KHWAJA, Jt. Secy.

Foot Note:—The Principal notification was published vide No. S.O. 60 (E) dated 27th January, 1994 and subsequently amended vide No. S.O. 356(E) dated 4th May, 1994.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 319(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियाँ इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट तापीय विद्युत संयंत्रों के संबंध में इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित और उसमें सुधार करने के लिए उपाय करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उसे समाप्त करने के संबंध में हैं, राज्य सरकारों द्वारा भी प्रयोग की जाएगी जो सभी भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 के रूप में अधिसूचित है।

अनुसूची-1

राज्य सरकार से पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा करने वाले तापीय विद्युत संयंत्रों का प्रवर्ग

I. सहउत्पादन कैप्टिव संयंत्र :

- सहउत्पादन संयंत्र: स्थापित क्षमताओं को ध्यान में रखे बिना सभी सहउत्पादन संयंत्र।
- कैप्टिव विद्युत संयंत्र: 250 मैगावाट तक (कोयला और गैस/नेपथा पर आधारित दोनों) जो पृथक् रूप से स्थापित किए गए हैं और जो मुख्य उद्योग के साथ नहीं हैं।

II. उपयोगिता परियोजना :

- 500 मैगावाट तक कि कोयले पर आधारित ऐसे संयंत्र जिनमें संवेदनशील क्षेत्रों के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए फ्लाइइंग बैड टैक्नालाजी का प्रयोग किया जाता है।
- 250 मैगावाट तक के कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र जिनमें परंपरागत प्रौद्योगिक का प्रयोग किया जाता है।
- 500 मैगावाट तक के गैस/नेपथा पर आधारित संयंत्र।

टिप्पण:

किसी आरक्षित वन परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य बायोस्फेयर आरक्षित और संकटपूर्ण प्रदूषित क्षेत्र आते हैं, की सीमा के 25 कि.मी. अर्ध व्यास के भीतर और अंतराज्यीय सीमा के 50 कि.मी. के भीतर स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति लेनी होगी।

अनुसूची-2

परियोजनाओं की पर्यावरण अनापत्ति की बांछा के लिए प्रक्रिया

- (1) कोई व्यक्ति जो अनुसूची-1 में उल्लिखित किसी प्रवर्ग का

तापीय विद्युत संयंत्र प्रस्थापित करने का इच्छुक है वह राज्य सरकार के पर्यावरण विषय से संबंधित विभाग को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

- (2) आवेदन इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप "क" में किया जाएगा और इसके साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न होगी जिसमें अन्य बातों के साथ एक पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंध रेखांक संलग्न होगा जो समय-समय पर राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी किए गए मानदंडों के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

- (3) ऐसे मामले जो अपर्याप्त या अपूर्ण आंकड़ों और क्रियान्वयन योजनाओं को प्रस्तुत करने के कारण खारिज कर दिए गए हैं जब भी संपूर्ण आंकड़ों और क्रियान्वयन योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी, पर पुनर्विलोकित किए जा सकेंगे। दूसरी बार अपूर्ण आंकड़ों प्रस्तुत किया जाना, स्वयं में, राज्य सरकार द्वारा मामले को संक्षिप्त तौर पर खारिज किए जाने के लिए एक पर्याप्त कारण होगा।

2. गतमुख तापीय विद्युत संयंत्रों के मामले में जब राज्य सरकार कोई अन्वेषण या सर्वेक्षण करती है, आवेदक राज्य सरकार को परियोजना का स्थल और उसकी प्रास्थिति की सूचना देगा। राज्य सरकार प्रस्तावित स्थल के बारे में उसकी उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में अधिकतम 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने विनिश्चय की संसूचना देगी। उक्त स्थल अनापत्ति मंजूर क्षमता के लिए स्वीकृत की जाएगी और यह परियोजना के निर्माण/प्रचालन के प्रारंभ से पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमन्य होगी।

3. (1) आवेदक सम्बद्ध पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट रूप में केवल सार्वजनिक सुनवाई पूरी करने के पश्चात् ही स्थापन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से लिए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र का, विशेषज्ञों की समिति जो राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट है, से परामर्श करके, राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन और निर्धारण किया जाएगा।

(3) उक्त विशेषज्ञों की समिति को यथास्थिति, कार्यस्थल या कारखाना परिसरों में प्रवेश या निरीक्षण का, संयंत्र से संबंधित प्रचालनों के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् या उनके दौरान किसी भी समय पूर्ण अधिकार होगा।

(4) पर्यावरण विषय से संबंधित राज्य सरकार का विभाग आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजों और आंकड़ों को, जो कार्यस्थलों पर निरीक्षण के दौरान और प्रभावित आबादी और पर्यावरण समूह से बातचीत करके इकट्ठे किए गए हैं, यदि आवश्यक हो, तकनीकी निर्धारण पर आधारित सिफारिशों का एक सेट

तैयार करेगा।

(5) निर्धारण आवेदक से अपेक्षित दस्तावेज और आंकड़ों की प्राप्ति से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा और उसके पश्चात् इसका विनिश्चय तीस दिनों के भीतर संसूचित किया जाएगा।

(6) मंजूर की गई पर्यावरण अनापत्ति, परियोजना के निर्माण या प्रचालन प्रारंभ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमन्य होगी।

4. तथ्यागत आंकड़ों को छुपाना या झूठे, भ्रामक आंकड़ों या रिपोर्ट, विनिश्चय या सिफारिश को प्रस्तुत किए जाने पर परियोजना नामंजूर कर दी जाएगी और यदि झूठे आंकड़ों के आधार पर पूर्व में अनुमोदन दिया जा चुका है तो उसे प्रतिसंगृहीत कर लिया जाएगा।

अनुसूची-3

[अनुसूची 2 के पैरा-3 का उप-पैरा (2) देखिए]

- समितियों में निम्नलिखित क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे :—
 - पारिस्थितिक तंत्र प्रबन्ध
 - वायु जल प्रदूषण नियंत्रण
 - जल संसाधन प्रबन्ध
 - वनस्पतिजात प्राणिजात संरक्षण और प्रबन्ध
 - भूमि प्रयोग योजना
 - सामाजिक विज्ञान पुनर्वास
 - परियोजना मूल्यांकन
 - पारिस्थितिकी
 - पर्यावरणीय स्वास्थ्य
 - विषय क्षेत्र विशेषज्ञ
 - गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित व्यक्ति।
- अध्यक्ष, उत्कृष्ट और अनुभवी परिस्थिति-विज्ञानी या पर्यावरणीविद या तकनीकी व्यावसायिक या सुसंगत विकास क्षेत्र में वृहत् प्रबंधकीय अनुभव का होगा।
- प्रभाव निर्धारण अभिकरण केन्द्र/राज्य का प्रतिनिधि सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- अध्यक्ष और सदस्य प्रतिनिधियों के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर वैयक्तिक हैसियत से कार्य करेंगे।
- किसी समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

प्ररूप-क

आवेदन-प्ररूप

- (क) प्रस्तावित परियोजना का नाम व पता :
- (ख) परियोजना की अवस्थिति :
स्थान का नाम :
जिला : तहसील :

- अध्दांश / रेखांश:
निकटतम विमान पत्तन/रेल स्टेशन :
- (ग) जांच किए गए वैकल्पिक स्थल तथा प्रस्तावित स्थल का चयन करने के लिए कारण :
- (घ) क्या यह स्थल स्थानीय भूमि प्रयोग योजना के अनुसार अनुबद्ध भूमि प्रयोग के अनुरूप है ?
2. परियोजना के उद्देश्य :
3. (क) अपेक्षित भूमि :
कृषि भूमि :
वन भूमि तथा वनस्पति का घनत्व :
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
- (ख) (1) आवाह क्षेत्र/प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. की परिधि में भूमि प्रयोग :
(2) क्षेत्र की स्थलकृति, जिसमें ढाल पहलू और ऊंचाई उपदर्शित की गई हो :
(3) प्रस्तावित भूमि का क्षण वर्गीकरण :
- (ग) 10 कि.मी. की परिधि में विद्यमान प्रदूषण स्रोत तथा वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता पर उनका प्रभाव :
(घ) निकटतम राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्य / जीवमंडल आरक्षित / स्मारकों ऐतिहासिक स्थलों/आरक्षित वनों की दूरी :
(ङ) खादानों/उधार क्षेत्रों के लिए पुनरुद्धार योजना :
(च) हरित पट्टी योजना :
(छ) प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना :
4. जलवायु और वायु गुणवत्ता :
(क) स्थल पर पदनारस :
(ख) अधिकतम/न्यूनतम/औसत वार्षिक तापमान :
(ग) प्रतिलोमन की आवृत्ति :
(घ) चक्रवातों/तूफानों/बादल फटने की आकृति :
(ङ) परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़े :
(च) परियोजना से एस पी एस, गैस (सी ओ सी ओ₂, एस ओ₂, एन ओ₂ एक्स सी एच एन आदि) के उत्सर्जन की प्रकृति और सान्द्रण ।
5. जल सन्तुलन :
(क) स्थल पर जल सन्तुलन :
(ख) क्षीण मौसम में जल की उपलब्धता :
जल की आवश्यकता :
(ग) प्रतियोगी उपयोक्ताओं सहित दोहन किए जाने वाले स्रोत (नदी, झील, भूमि सार्वजनिक आपूर्ति)
(घ) जल गुणवत्ता :
(ङ) पिछले 15 वर्षों में भूमि जल की गुणवत्ता और मात्रा में देखे गए परिवर्तन तथा वर्तमान चार्जिंग और निकासी के ब्यारे
(च) (1) शोधन ब्यौरे सहित छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा
(2) ठोस अपशिष्टों के व्ययन से पूर्व और पश्चात् अभिग्राही बॉडी में जल की मात्रा और गुणवत्ता :
- (3) भूमि पर छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा और भूमि की किस्म :
(छ) (1) आवश्यक आवाह शोधन योजना सहित जलाशय जल गुणवत्ता के ब्यौरे :
(2) कमांड क्षेत्र विकास योजना
6. ठोस अपशिष्ट :
(क) उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की प्रकृति और मात्रा :
(ख) ठोस अपशिष्ट निपटान का तारीख ।
7. शोर और कंपन :
(क) शोर और कंपन के स्रोत :
(ख) परिवेशी शोर स्तर :
(ग) शोर और कंपन नियंत्रण के प्रस्तावित उपाय :
(घ) अवतलन समस्या, यदि कोई हो और उसके नियंत्रण के उपाय
8. बिजली की आवश्यकता, जिसमें आपूर्ति के स्रोत का उल्लेख हो, यदि कैप्टिव बिजली इकाई लगाने का प्रस्ताव हो तो पूरा पर्यावरणीय ब्यौरा अलग से भेजें ।
9. लगाया जाने वाला चरम श्रमिक बल, जिसमें निम्न ब्यौरा दिया जाए :
—अपशिष्ट जल/वायु/मृदा जनित रोगों के कारण क्षेत्र में स्थानिक स्वास्थ्य समस्याएं ।
—विद्यमान और प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली ।
10. (क) विस्थापित होने वाले गांवों और लोगों की संख्या
(ख) पुनर्वास बृहत योजना ।
11. जोखिम निर्धारण रिपोर्ट तथा विपदा प्रबन्ध योजना ।
12. (क) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा) :
(ख) पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना (समय-समय पर जारी मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार तैयार) :
(ग) विस्तृत व्यावहारिकता रिपोर्ट :
(घ) विधिवत् भरी हुई प्रश्नावली ।
- केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट ।
13. पर्यावरणीय प्रबन्ध कक्ष का ब्यौरा ।
- मैं यह वचन देता हूँ कि ऊपर दिए गए आंकड़े और सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि प्रस्तुत किए गए आंकड़ों /सूचना का कोई भाग किसी भी समय मिथ्या या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को नामंजूर कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गई अनापत्ति, यदि कोई हो, को हमारे जोखिम और लागत पर वापस लिया जा सकेगा ।
- तारीख :
स्थान :
- आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम और पूरे पते सहित)
आवेदक जिस संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है उस संगठन की मोहर

टिप्पण :—ऐसे मदों की बाबत जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक की घोषणा के अनुसार आंकड़े अपेक्षित नहीं हैं या उपलब्ध नहीं हैं तो परियोजना पर उसी आधार पर विचार किया जाएगा।

अनुसूची-4

[अनुसूची-2 का पैरा 3, उप पैरा (2) देखिए]

लोक सुनवाई के लिए प्रक्रिया :

(1) लोक सुनवाई की प्रक्रिया—जो कोई परियोजना के पर्यावरण संबंधी निर्वाधन के लिए आवेदन करेगा वह संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेजों के बीस सैट प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

- (i) एक कार्यपालक सार, जिसमें परियोजना की मुख्य बातें अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में होंगी।
- (ii) जहां मल का निस्सारण, व्यापार बहिस्त्रोव, जल-संसाधन किसी रूप में अपेक्षित है वहां जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण नियम, 1975 के अधीन विहित प्ररूप-XIII
- (iii) जहां किसी प्रसंस्करण, संक्रिया या उद्योग में उत्सर्जन का उन्मोचन अन्तर्वर्तित है वहां वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संघ राज्य क्षेत्र नियम, 1983 के अधीन विहित प्ररूप-1।
- (iv) कोई अन्य जानकारी या दस्तावेज, जो बोर्ड की राय में आवेदन के संबंध में उनके अन्तिम निपटारे के लिए आवश्यक है।

(2) लोक सुनवाई की सूचना—(i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण संबंधी लोक सुनवाई की सूचना देगा, जो परियोजना के आसपास के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो समाचारपत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिनमें से एक संबंधित स्थान की विशिष्ट भाषा में होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लोक सुनवाई की सूचना देगा। (को) परियोजना (के) आसपास की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख करेगा। अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर जनता के सुझाव, विचार टीका-टिप्पणियां और आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे।

(ii) ऐसे सभी व्यक्ति, जिनमें वास्तविक निवासी, पर्यावरण संबंधी समूह और परियोजना स्थल (विस्थापन-स्थल) स्थलों पर स्थित अन्य व्यक्ति भी हैं, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, लोक सुनवाई में भाग ले सकते हैं। वे राज्य प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड को मौखिक/लिखित सुझाव भी दे सकते हैं।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजन के लिए व्यक्ति से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

- (क) कोई व्यक्ति जिसके पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के दिए जाने से प्रभावित होने की संभावना है;
- (ख) कोई व्यक्ति जो ऐसी परियोजना का, जिसकी बाबत पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, स्वामी हैं या उस पर उसका नियंत्रण है;
- (ग) व्यक्तियों का ऐसा कोई संगम, चाहे निगमित हो या नहीं जिसके पर्यावरण के क्षेत्र में परियोजना और/या कार्यकरण से प्रभावित होने की संभावना है;
- (घ) किसी भाग के भीतर, जिसकी स्थानीय सीमाएं ऐसे पड़ोस के

अन्तर्गत हैं जिसमें परियोजना को लगाए जाने का प्रस्ताव है, कोई स्थानीय प्राधिकरण।

(3) लोक सुनवाई पैनल की संरचना—लोक सुनवाई पैनल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- (i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि;
- (ii) जिला कलक्टर या उसका नामनिर्देशित;
- (iii) विद्युत के विषय पर कार्यवाई करने वाले राज्य सरकार के प्रतिनिधि;
- (iv) पर्यावरण के विषय पर कार्यवाई करने वाले राज्य सरकार के प्रतिनिधि;
- (v) नगरपालिकाओं या पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों में तीन से अनधिक प्रतिनिधि;
- (vi) जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले क्षेत्र के तीन से अनधिक ज्येष्ठ नागरिक।

(4) कार्यपालक सार तक पहुंच :—संबंधित व्यक्तियों की निम्नलिखित स्थानों पर परियोजना के सार तक पहुंच की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात् :—

- (i) जिला कलक्टर का कार्यालय;
- (ii) जिला उद्योग केन्द्र;
- (iii) जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या, यथास्थिति, नगरनिगम/स्थानीय निकाय के आयुक्त के कार्यालय में;
- (iv) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय या इसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में;
- (v) पर्यावरण के विषय पर कार्यवाई करने वाले राज्य सरकार के संबंधित विभाग में।

[सं. जैड-12013/4/89-आई०ए०1]

आर०एच० ख्वाजा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 319 (E).— In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to take measures for protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution be exercisable also by the State Government as notified in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994 in relation to the Thermal Power Plants specified in Schedule-I annexed to this notification subject to the conditions and limitations specified in Schedule-II annexed to this notification.

SCHEDULE-I

Category of Thermal Power Plants requiring environmental clearance from the State Government.

I. Co-generation Captive Plants:

- | | |
|--------------------------|--|
| (i) Co-Generation Plants | All Co-generation Plants irrespective of the installed capacities. |
|--------------------------|--|

- (ii) Captive Power Plants: Upto 250 MW (both coal and gas/naphtha based) coming up separately and not along the main industry.

II. Utility Projects:

- (i) Coal based plants upto 500 MW using fluidized bed technology subject to sensitive areas restrictions.
- (ii) Coal based Power Plants upto 250 MW using conventional technologies.
- (iii) Gas/Naphtha based plants upto 500 MW.

Note: Any project proposed to be located within the radius of twenty five km boundary of reserved forests, ecologically sensitive area which may include National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, critically polluted area and within fifty kms of inter-state boundary shall require environmental clearance from the Central Government.

SCHEDULE-II

Procedure for seeking environment clearance of projects.

- I. (1) Any persons who desires to establish a thermal power plant of any category mentioned in Schedule-I, shall submit an application to the Department of the State Government dealing with the subject of Environment.
- (2) The application shall be made in the Form 'A' specified in Schedule-II annexed to this notification and shall be accompanied by a detailed project report which shall, inter alia, include an Environmental Impact Assessment Report and an Environment Management Plan prepared in accordance with the guidelines issued by the State Department of Environment from time to time.
- (3) Cases rejected due to submission of insufficient or inadequate data and Action Plans may be reviewed as and when submitted with complete data and Action Plans. Submission of incomplete data for the second time would itself be a sufficient reason for the State Government to reject the case summarily.
2. In case of the pit-head thermal power plants, the applicant shall intimate the location of the project site to the State Government while initiating any investigation and surveys. The State Government will convey a decision regarding suitability or otherwise of the proposed site within a maximum period of thirty days. The said site clearance will be granted for a sanctioned capacity and it will be valid for a period of five years for commencing the construction or operation of the project.
3. (1) The applicant shall obtain No Objection Certificate from the concerned Pollution Control Board. The State Pollution Control Board shall issue No Objec-

tion Certificate to establish only after completing public hearing as specified in Schedule-IV annexed to this notification.

- (2) The reports submitted with the application, and No Objection Certificate from the State Pollution Control Board shall be evaluated and assessed by the State Government, in consultation with a Committee of experts which shall be constituted by the State Government as specified in Schedule-III appended to this notification.
- (3) The said Committee of experts shall have full right of entry and inspection of the site or, as the case may be, factory premises at any time prior to, during or after the commencement of the operations relating to the plant.
- (4) The State Government Department dealing with the subject of Environment shall prepare a set of recommendations based on technical assessment of documents and data furnished by the applicant supplemented by data collected during visits to sites, if undertaken and interaction with affected population and environment groups, if necessary.
- (5) The assessment shall be completed within a period of ninety days from receipt of the requisite documents and data from the applicant and decision conveyed within thirty days thereafter.
- (6) The environmental clearance granted shall be valid for a period of five years from commencement of the construction or operation of the project.

4. Concealing factual data or submission of false, misleading data or reports, decisions of recommendations would lead to the project being rejected. Approval, if granted, earlier on the basis of false data, can also be revoked.

(FORM A)

APPLICATION FORM

1. (a) Name and Address of the project proposed :
 - (b) Location of the project:

Name of the place:

District, Tehsil:

Latitude/Longitude:

Nearest Airport/Railways Station:
 - (c) Alternate sites examined and the reasons for selecting the proposed site:
 - (d) Does the site conform to stipulated land use as per local land use plan:
2. Objectives of the project:
 3. (a) Land Requirement:

Agriculture Land:

Forest land and Density of vegetation other (specify):
 - (b) (i) Land use in the Catchment/within 10 Kms. radius of the proposed site:

- (ii) Topography of the area indicating gradient, aspects and altitude;
 - (iii) Erodibility classification of the proposed land;
 - (c) Pollution sources existing in 10 Km radius and their impact on quality of air, water and land;
 - (d) Distance of the nearest National Park/Sanctuary /Biosphere Reserve/Monuments/heritage site/Reserve Forest;
 - (e) Rehabilitation plan for quarries/borrow areas;
 - (f) Green belt plan;
 - (g) Compensatory afforestation plan;
4. Climate and Air Quality:
- (a) Windrose at site;
 - (b) Max/Min/Mean annual temperature;
 - (c) Frequency of inversion;
 - (d) Frequency of cyclones/tornadoes/cloud burst;
 - (e) Ambient air quality data;
 - (f) Nature and concentration of emission of SPM, Gas (CO, CO₂, NO_x, CH₄ etc.) from the project;
5. Water balance:
- (a) Water balance at site;
 - (b) Lean season water availability:
Water Requirement;
 - (c) Source to be tapped with competing users (River, Lake, Ground, Public supply);
 - (d) Water quality;
 - (e) Changes observed in quality and quantity of ground water in the last 15 years and present charging and extraction details;
 - (f) (i) Quantum of waste water to be release with treatment details;
 - (ii) Quantum of quality of water in the receiving body before and after disposal of solid wastes;
 - (iii) Quantum of waste water to be released on land and type of land;
 - (g) (i) Details of reservoir water quality with necessary Catchment Treatment Plan;
 - (ii) Command Area Development Plan;
6. Solid wastes :
- (a) Nature and quantity of solid wastes generated ;
 - (b) Solid waste disposal method;
7. Noise and Vibrations:
- (a) Sources of Noise and Vibrations;
 - (b) Ambient noise level;
 - (c) Noise and Vibration control measures proposed;
 - (b) Subsidence problem if any with control measures:
- 927 21/9) - 2

8. Power requirement indicating source of supply : Complete environmental details to be furnished separately, if captive power unit proposed;
9. Peak labour force to be deployed giving details of :
Endemic health problems in the area due to waste water/air/soil borne diseases:
Health care system existing and proposed;
10. (a) Number of villages and population to be displaced:
(b) Rehabilitation Master Plan;
11. Risk Assessment Report and Disaster Management Plan;
12. (a) Environmental Impact Assessment:
(b) Environment Management Plan;
(c) Detailed Feasibility Report;
(d) Duly filled in questionnaire;

Report prepares as per guidelines issued by the Central Government in the MOEF from time to time;

13. Details of Environmental Management Cell:

I hereby give an undertaking that the data and information given above are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data/information submitted is found to be false or misleading at any stage, the project be rejected and the clearance given, if any, to the project is likely to be revoked at our risk and cost.

Signature of the applicant
with name and full address

Given under the seal of Organisation
on behalf of whom the applicant is signing.

Date :

Place :

In respect to item for which data are not required or is not available as per the declaration of project proponent, the project would be considered on that basis.

SCHEDULE-III

[See Sub. para (2), Para 3 of Schedule-II]

COMPOSITION OF THE EXPERT COMMITTEES FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

1. The Committees will consist of experts in the following disciplines:
 - (i) Eco-System Management
 - (ii) Air/Water Pollution Control
 - (iii) Water Resource Management
 - (iv) Flora/Fauna Conservation and management
 - (v) Land Use Planning
 - (vi) Social Sciences/Rehabilitation

- (vii) Project Appraisal
 - (viii) Ecology
 - (ix) Environmental Health
 - (x) Subject Area Specialists
 - (xi) Representatives of NGOs/persons concerned with environmental issues.
2. The Chairman will be an outstanding and experienced ecologist or environmentalist or technical professional with wide managerial experience in the relevant development sector.
 3. The representative of Impact Assessment Agency will act as a Member-Secretary.
 4. Chairman and Members will serve in their individual capacities except those specifically nominated as representatives.
 5. The Membership of a Committee shall not exceed 15.

“SCHEDULE-IV

[See para 3, subparagraph (2) of Schedule-II]

PROCEDURE FOR PUBLIC HEARING

(1) **Process of Public Hearing:**—Whoever apply for environmental clearance of projects, shall submit to the concerned State Pollution Control Board twenty sets of the following documents namely:—

- (i) An Executive summary containing the salient features of the project both in English as well as local language.
- (ii) Form XIII prescribed under Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975 where discharge of sewage, trade effluents, treatment of water in any form, is required.
- (iii) Form I prescribed under Air (Prevention and Control of Pollution) Union Territory Rules, 1983 where discharge of emissions are involved in any process, operation or industry.
- (iv) Any other information or document which is necessary in the opinion of the Board for their final disposal of the application.

(2) **Notice of Public Hearing:**—(I) The State Pollution Control Board shall cause a notice for environmental public hearing which shall be published in at least two newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned. State Pollution Control Board shall mention the date, time and place of public hearing. Suggestions, views, comments, and objections of the public shall be invited within thirty days from the date of publication of the notification.

(ii) All persons including bonafide residents, environmental groups and others located at the project site/sites of displacement/sites likely to be affected can participate in the public hearing. They can also make oral/written suggestions to the State Pollution Control Board.

Explanation :—For the purpose of the paragraph person means—

- (a) any person who is likely to be affected by the grant of environmental clearance;
- (b) any person who owns or has control over the project with respect to which an application has been submitted for environmental clearance;
- (c) any association of persons whether incorporated or not likely to be affected by the project and/or functioning in the field of environment;
- (d) any local authority within any part of whose local limits is within the neighbourhood wherein the project is proposed to be located.

(3) **Composition of public hearing panel:**—The composition of Public Hearing Panel may consist of the following, namely:—

- (i) Representative of State Pollution Control Board;
- (ii) District Collector or his nominee;
- (iii) Representative of State Government dealing with the subject of power
- (iv) Representative of Department of the State Government dealing with Environment;
- (v) Not more than three representatives of the local bodies such as Municipalities or Panchayats;
- (vi) Not more than three senior citizens of the area nominated by the District Collector.

(4) **Access to the Executive Summary:**—The concerned persons shall be provided access to the Executive Summary of the Project at the following places namely:—

- (i) District Collector Office;
- (ii) District Industry Centre;
- (iii) In the Office of the Chief Executive Officer of Zila Parishad or Commissioner of the Municipal Corporation/Local body as the case may be;
- (iv) In the head office of the concerned State Pollution Control Board and its concerned Regional Office;
- (v) In the concerned Department of the State Government dealing with the subject of environment”.

[No. Z-12013/4/89-I. A. I]
R. H. KHWAJA, Jt. Secy.